राजस्थान सरकार
आपदा प्रबन्धन एवं सहायता विभाग

दिनांक 23.8.2010 को माननीय मुख्यमंत्री महोदय की अध्यक्षता में आयोजित राज्य आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण की बैठक का कार्यवाही विवरण

दिनांक 23.8.2010 को राज्य आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण की बैठक माननीय मुख्यमंत्री महोदय की अध्यक्षता में आयोजित हुई, जिसमें **परिशिष्ट–अ** के अनुसार माननीय मंत्रीगण/अधिकारीगण द्वारा भाग लिया गया।

बैठक के प्रारम्भ में शासन सचिव, आपदा प्रबन्धन एवं सहायता द्वारा माननीय मुख्यमंत्री, माननीय मंत्रीगण एवं उपस्थित अधिकारीगण का स्वागत किया। तदुपरान्त प्रदेश में इस वर्ष मानसूनी बारिश का लेखा–जोखा प्रस्तुत किया तथा जिलेवार वर्षा की स्थिति का विवरण देते हुये यह उल्लेख किया कि बाड़मेर जिले में नरेगा के तहत निर्मित 44779 टांकों में 30000 लीटर प्रति टांका वर्षा जल एकत्रित हो जाने से वहां के निवासियों के लिये 2 वर्ष हेतु पर्याप्त जल संग्रहण हो गया है। इसी प्रकार अजमेर जिले में 6333 जल संग्रहण ढांचों में 3083 हेक्टेयर मीटर पानी का भराव हो चुका है। इस जल से भूजल स्तर में 2 से 3 मीटर तक वृद्धि की उम्मीद है तथा लगभग 3 लाख हेक्टेयर कृषि भूमि में सिंचाई की जा सकेगी। चूरू जिले में भी 5626 जल संग्रहण कार्य किये गये हैं, जिनमें अच्छी वर्षा से पानी की आवक होने के कारण जल समस्या का समाधान होगा। पाली जिले में 7809 जल संग्रहण के कार्य स्वीकृत किये गये, जिनमें अब अब 1973 कार्य पूर्ण हुये हैं, जिससे 9745 एमसीफीट पानी भराव क्षमता में वृद्धि हुई है, जिसके फलस्वरूप 55190 हेक्टेयर कृषि भूमि लाभान्वित होगी। इसके पश्चात् उन्होंने राजस्थान में विभिन्न बांधों में जल भंडारण की स्थिति का लेखा–जोखा रखा तथा प्रदेश में मानसून के आगामी सप्ताह एवं आगामी माह की वर्षा संभावना पर प्रकाश डाला।

मौसम विभाग, जयपुर के निदेशक द्वारा मानसून की अब तक की स्थिति एवं भविष्य की संभावना पर प्रकाश डालते हुये पावर पॉइन्ट के माध्यम से प्रस्तुतिकरण दिया गया। अध्यक्ष महोदय द्वारा खास तौर पर सामान्य से कम वर्षा वाले जिलों और पूरे प्रदेश में मानसून की आगे की संभावनाओं पर जानकारी चाही। राज्य के बांधों के अब तक भी काफी हद तक खाली पड़े होने पर चिन्ता जाहिर करते हुये, बांधों में अवशेष अवधि में पानी की आवक के सम्बन्ध में संभावना पूछी। मौसम विभाग के निदेशक का आकलन था कि मानसून की शेष अवधि में लगभग सामान्य वर्षा होने की संभावना है। बांधों में विशेष पानी आने की संभावना कम ही है।

राज्य के 22 बृहद बाँधों में अब तक इस वर्ष उनकी पूर्ण भराव क्षमता का 42.93% पानी की आवक हुई है, जबकि गत वर्ष इस अवधि तक इन बांधों में 42.70% पानी की आवक हुई थी।

कृषि विभाग की ओर से बतया गया कि प्रदेश में हरा चारा पर्याप्त मात्रा में उत्पन्न हो गया है, जिसके कारण चारे के भाव काफी हद तक नीचे आ गये हैं और पशुपालन की दृष्टि से किसान काफी हद तक सुरक्षित महसूस कर रहे हैं। दूसरी ओर, अब तक राज्य में फसल भी काफी अच्छी बनी हुई है। ग्रामीण विकास मंत्री महोदय द्वारा बताया गया कि कोटा एवं उदयपुर संभाग में लगातार दूसरे साल वर्षा सामान्य से

कम हुई है तथा बांध भी काफी हद तक खाली हैं। अगले सीजन में इस कारण चुनौतियों आ सकती है। अतः आवश्यक योजना तैयार की जानी चाहिये।

अध्यक्ष महोदय द्वारा खेतड़ी क्षेत्र में अत्यधिक वर्षा से हुये नुकसान पर गहरी चिन्ता व्यक्त की। राज्य के अलग–अलग हिस्सों में जान–माल का जो भी नुकसान हुआ है उसका शीघ्र सर्वे करवाने के निर्देश दिये। साथ ही आपदाओं से जिन लोगों की जान चली गई है उनके परिजनों को नियमानुसार सहायता तुरन्त उपलब्ध कराने के निर्देश दिये। सीकर के नीमकाथाना क्षेत्र में जिन लोगों को सुरक्षित स्थानों पर स्थानांतरित (shift) किया गया है उनके लिये भी आवश्यक व्यवस्था करने के निर्देश दिये। जिलों में, जहां–जहां मापदण्डानुसार बजट की आवश्यकता है वहां–वहां, तुरन्त बजट उपलब्ध कराने के भी निर्देश दिये।

इसके उपरान्त उन्होंने चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग से स्वाइन फ्लू महामारी से बचाव के सम्बन्ध में अभी तक किये गये प्रयासों पर विस्तार से जानकारी प्राप्त की। साथ ही मलेरिया व डेंगू नियंत्रण के सम्बन्ध में भी गम्भीरता से प्रयास करने के निर्देश दिये। इन बीमारियों के लिये अन्य पड़ौसी राज्यों की तुलना में अनुसंधान व उपचार की अच्छी सुविधायें मुहैया करवाने के निर्देश दिये। विभाग को यह भी पता करने के निर्देश दिये कि स्वाइन फ्लू बीमारी फैलने के वास्तविक स्त्रोत क्या हैं, ताकि उन पर नियंत्रण किया जा सके। इस सम्बन्ध में उन्होंने प्रचार–प्रसार के जरिये तथा गैर सरकारी स्वयं सेवी संस्थाओं का सहयोग लेकर लोगों में जागरूकता पैदा करने की आवश्यकता पर बल दिया। इस सम्बन्ध में पल्स पोलियो की तरह अभियान चलाकर लोगों में जागरूकता पैरा करने की आवश्यकता पर उन्होंने बल दिया। उन्होंने विभाग को यह भी कहा कि वंचित/जरूरतमंद वर्गों को निःशुल्क टीके लगाने की संभावना पर भी विचार किया जावे।

तत्पश्चात् अध्यक्ष महोदय द्वारा विद्युत आपूर्ति की स्थिति की समीक्षा की। साथ ही आगामी रबी सीजन के लिये पर्याप्त बिजली की अभी से व्यवस्था करने के ऊर्जा विभाग को निर्देश दिये। ग्रामीण विकास मंत्री महोदय द्वारा स्थानीय बिजली आपूर्ति सम्बन्धी समस्याओं के भी तत्परता से निराकरण की ओर विभाग का ध्यान आकर्षित किया। अध्यक्ष महोदय द्वारा स्प्रिंकलर सिस्टम के कनेक्शन सम्बन्धी समस्या का अध्ययन करवाकर इस हेतु अलग से मीटिंग बुलाने के ऊर्जा विभाग को निर्देश दिये।

खाद्य विभाग द्वारा खरीफ 2067 में बाजरे की अच्छी फसल के मध्यनजर सरकारी स्तर पर खरीद की संभावना के सम्बन्ध में अपना आंकलन पेश किया। बाजरे के बाजार भाव एवं केन्द्र द्वारा घोषित समर्थन मूल्य से अध्यक्ष महोदय को अवगत करवाया। अध्यक्ष महोदय ने निर्देश दिये कि कृषि विभाग एवं खाद्य विभाग फसल उत्पादन का पूरा आकलन कर, गत वर्षों के अनुभवों के आधार पर, प्रकरण का विस्तार से परीक्षण कर अपने सुझाव प्रस्तुत करें। खाद्य विभाग द्वारा राशन वितरण में सरकारी कर्मचारियों द्वारा शुरू की गई निगरानी व्यवस्था की प्रगति से अवगत कराया। अध्यक्ष महोदय ने प्रमुख सचिव खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति को निर्देशित किया कि उनके विभाग द्वारा खाद्य आपूर्ति निगम गठित करने का कार्य शीघ्र पूर्ण करें। अध्यक्ष महोदय ने बैठक के दौरान हुई चर्चा के क्रम में यह निर्देश दिये कि ग्राम सेवकों की हड़ताल हेतु प्रकरण का पूरा अध्ययन कर अलग से बैठक करवाकर ग्रामीण विकास विभाग फैसला करावें।

प्रदेश में बारिश के कारण जहां–जहां सड़के क्षतिग्रस्त हो गई है उनके लिये अभी से आंकलन करवाकर योजना बनाने के निर्देश अध्यक्ष महोदय द्वारा नगरीय विकास विभाग आदि को दिये। उन्होंने यह भी कहा कि इनकी मरम्मत के लिये सीआरएफ से जहां–जहां, गाइडलाइन्स को ध्यान में रखकर, राशि दी जा सकती है उनका परीक्षण करवा लिया जावे। अध्यक्ष महोदय ने अतिरिक्त मुख्य सचिव (वित्त) को निर्देशित किया कि वो इस संबंध में सार्वजनिक निर्माण विभाग, जयपुर, नगरीय विकास विभाग, स्वायत्त शासन विभाग तथा आपदा प्रबन्धन एवं सहायता विभाग के साथ समन्वय बैठक आयोजित कर 1 सप्ताह में कार्य योजना तैयार करें।

कृषि मंत्री महोदय द्वारा फसल बीमा की संभावनाओं के सम्बन्ध में अवगत कराते हुये बताया कि डीडवाना आदि कुछ क्षेत्रों में राज्य कर्मचारियों द्वारा गिरदावरी में तो 75 प्रतिशत या उससे अधिक खराबा दिखा दिया है जबकि क्रॉप कटिंग के नतीजों में अच्छी पैदावार दिखा दी गई है जिससे किसानों को फसल बीमे का भुगतान रुक गया है। इस पर अध्यक्ष महोदय ने प्रकरण को दिखवाने के निर्देश दिये। दूसरी ओर यह भी बताया गया कि भारत सरकार ने चूंकि अब तक 700 करोड़ के विरूद्ध मात्र 130 करोड़ की राशि ही जारी की है इस कारण से भी किसानों को फसल बीमा का भुगतान रुका है। अध्यक्ष महोदय ने मामले को भारत सरकार स्तर से संपर्क कर शीघ्र समाधान करवाने के निर्देश दिये।

जल संसाधन विभाग द्वारा अत्यधिक वर्षा से टूटे हुये कई बांधों की मरम्मत के लिये सीआरएफ से राशि स्वीकृत करवाने की मांग की। इस पर अध्यक्ष महोदय ने निर्देश दिये कि पहले पूरा सर्वे करवा लिया जाये।

ग्रामीण विकास मंत्री महोदय द्वारा फसल में कीड़े लग जाने के कारण दवाइयों की जरूरत बताते हुये किसानों को इन बीमारियों पर नियमानुसार अनुदान दिलवाने की कृषि विभाग से मांग की। अध्यक्ष महोदय द्वारा शीघ्र कार्यवाही के निर्देश दिये। सहकारिता विभाग द्वारा कृषि ऋण वितरण की प्रगति से अवगत कराया गया। पशुपालन विभाग द्वारा पशुओं में बीमारियों की रोकथाम के लिये किये गये उपायों की जानकारी दी। अध्यक्ष महोदय ने निर्देश दिये कि जहाँ–जहाँ बाढ़ के कारण पशुधन को नुकसान हुआ है वहाँ–वहाँ सीआरएफ मापदण्डानुसार सहायता उपलब्ध करवाई जाये।

शासन सचिव, आपदा प्रबन्धन एवं सहायता द्वारा कृषि आदान अनुदान वितरण की प्रगति से अवगत कराया। बीकानेर, नागौर एवं डूंगरपुर जिलों में 2–5 हेक्टेयर वाले किसानों को कृषि आदान अनुदान वितरण में जिला प्रशासन स्तर पर किये जा रहे अनावश्यक विलम्ब की बात सामने आई । इस पर अध्यक्ष महोदय ने निर्देश दिये कि संबंधित जिला कलेक्टरों से बात कर कृषि आदान अनुदान का वितरण अब बिना और किसी विलम्ब के सुनिश्चित किया जाये।

अध्यक्ष महोदय द्वारा सभी विभागों को पूरी संवेदनशीलता और जागरूकता से बाढ़ आदि के परिप्रेक्ष्य में कार्य करते रहने के निर्देश दिये । साथ ही आपदा पीड़ितों को अविलम्ब सहायता मुहैया करवाने के अपने निर्देशों को दोहराया।

अन्त में अध्यक्ष महोदय को धन्यवाद के साथ बैठक समाप्त हुई ।

शासन उप सचिव